

an>

Title: Need to include the information regarding government schemes in educational curriculum.

**श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :** सभापति महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा जनहित में कई ऐतिहासिक योजनाएँ शुरू की गयी हैं, जिनका देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा खुले मन से स्वागत किया गया है। बैंक खाते खुलवाना हो, बीमा बचत, पेंशन की योजना हो, कौशल विकास की योजना हो या डिजिटल भारत योजना हो, देश के हर व्यक्ति के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कोई न कोई योजना के माध्यम से देश के गरीब से गरीब को मुख्य धारा में शामिल किये जाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन, धरातल पर उन योजनाओं की सफलता आज हम सब के सामने है। योजनाओं का पूर्णतः सफल होना, योजना का लाभ केवल लाभार्थियों तक पहुंचाने पर ही निर्भर करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका योजना की जानकारी पहुंचाने की है।

सरकारें इस विद्यालय पर सैंकड़ों-करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करती आ रही हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार की योजना का विवरण संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक विद्यालय के रूप में शामिल किया जाए जिससे छात्र-छात्राओं को उनके विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा इन सभी योजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्य आदि के बारे में अध्ययन कराया जाए, तो नःसन्देह इन योजनाओं की पहुंच आसानी से देश के हर घर में हो जाएगी। प्रत्येक घर में मौखिक जानकारी और लिखित जानकारी पहुंचाने का यह एकमात्र सुलभ रास्ता है, जिसमें देश के गरीबों को उन योजनाओं का फायदा पिछले 65 वर्षों तक नहीं मिला है, उनको फायदा मिलना शुरू होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को लागू किया है, उन योजनाओं का टारगेट था कि वे घर-घर तक पहुंचें और इसी वजह से इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अतः सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकारी योजनाओं को समावेश शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विशेष विद्यालय के रूप में किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद।